# राष्ट्रीय विकास में मेक इन इन्डिया का महत्व

**अर्पित चौधरी**
रुड़की।

"सोने की चिड़िया" नाम से विश्व में जाना जाने वाला भारत प्राचीन काल में एक सम्पन्न देश था। भारतीय कारीगरों द्वारा तैयार किए गए माल की अरब, मिश्र, रोम, फ्रांस तथा इग्लैंड में बहुत माँग थी। भारत से व्यापार करने के लिए विदेशी राष्ट्रों में होड़ लगी रहती थी। इसी कारण सन् 1600 ई० में इंग्लैंड में ईस्ट इन्डिया कम्पनी की स्थापना हुई। जहाँगीर के शासन काल में उसने भारत में व्यापार करने की अनुमति मांगी इस कम्पनी ने भारत की सम्पदा रेशम और मखमल का विदेश में व्यापार कर खूब समृद्धि पाई। जिसके परिणामस्वरूप अंग्रेज समृद्ध होते गए परन्तु कारीगरों को उचित श्रम मूल्य ना मिलने के कारण वे बेहाल होते गए। धीरे–धीरे उन्होंने अपना पुश्तैनी पेशा छोड़ दिया जिसका सीधा असर लघु उद्योगों पर पड़ा वे बन्द होते चले गए। देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने उद्योगों की स्थिति सुधारने एवं उनके विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं चलाई। इन योजनाओं से उद्योग आरम्भ तो हुए परन्तु बढ़ती जनसंख्या, अकुशल युवा वर्ग, रोजगार के कम अवसर, अपर्याप्त पूंजी सभी ने इनके विकास की दर को धीमा ही रहने दिया।

आधुनिक भारत में लगभग 80 करोड़ (800 मिलियन) नौजवान हैं जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है परन्तु उनमें से केवल 10 प्रतिशत नौजवान ही सही मानक पर प्रशिक्षित होकर व्यावसायिक तौर से कुशलतापूर्वक अपना कार्य कर सकते हैं। 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए देश का समुचित तकनीकी विकास के साथ–साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, उद्योग सभी क्षेत्रों में स्थायी विकास होना अत्यंत आवश्यक है। आज की आवश्यकता है कि युवा वर्ग को बेहतर तकनीकी शिक्षा, गुणवत्ता से भरपूर प्रशिक्षण मिले जिससे वह अपना कार्य पूरी निपुणता, ईमानदारी एवं सामर्थ्य से कर अपना एवं देश का चौमुखी विकास कर सकें।

संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान के अनुसार–"एक विकसित देश वह होता है जो अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित पर्यावरण में स्वतन्त्रता एंव स्वस्थ्य जीवन का आनंद लेने का अवसर देता है।" अर्थात देश तभी पूर्णतः विकसित होता है जब वह पूर्णतः आत्मर्निभर हो एवं उसके हर वर्ग का समुचित विकास हो।

भारत एक विकासशील देश है। भारत के उद्योगों की सकल घरेलू उत्पाद में केवल 15 प्रतिशत की भागेदारी है। इसका मुख्य कारण है कि भारत में व्यापार करना काफी जटिल है। विश्व बैंक ने वर्ष 2016 में 189 देशों का सर्वेक्षण कर फरवरी माह में "व्यापार में आसानी सूचकांक" जारी किया, जिसमें भारत का स्थान 130वां है। भारत को व्यापार के लिए सुविधापूर्वक बनाना आधुनिक समय की मांग है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस "मेक इन इन्डिया" अभियान की शुरूआत हुई।

"मेक इन इन्डिया" अभियान की शुरूआत भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 25 सितम्बर 2014 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन से की थी। इसका उद्देश्य जरूरत की एंव उत्तम गुणवत्ता वाली वस्तुओं का निर्माण ज्यादा से ज्यादा भारत में ही हो। इस योजना का कार्य भारत में व्यापार करने के इच्छुक विश्व के बड़े व्यावसायियों को विभिन्न व्यवसायों में पैसा लगाने के अवसर उपलब्ध कराना है। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि उत्पाद को तैयार करने में लगने वाली श्रम शक्ति भारतीय होगी।

इस योजना के लिए अब तक 930 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है सरकार इस योजना के लिए 581 करोड़ रूपये देगी। बाकी रूपये भारतीय एवं विदेशी कम्पनियाँ लगाएंगी। पूरी योजना में 20,000 करोड़ रूपये की लागत आने का अनुमान है। इसमें व्यापार हेतु 25 प्रमुख क्षेत्रों को चुना है; आटोमोबाइल, यातायात, सड़क और हाईवे, पर्यटन, रसायन, खनन रक्षा उपकरण, खाद्य, निर्माण, अन्तरिक्ष, वस्त्र कपड़ा, चमड़ा, मीडिया, स्वास्थ्य, कल्याण, बन्दरगाह, सूचना प्रोद्यौगिकी, अतिथि सत्कार, मनोरंजन, ताप विद्युत निर्माण, तेल गैस, अक्षय ऊर्जा, जैव प्रौद्योगिकी, विद्युत मशीनरी इत्यादि। भारत को वैश्विक उत्पादन का केन्द्र बनाने के उद्देश्य से चलाई गई इस योजना को सफल बनाने के लिए "मेक इन इन्डिया डॉट कॉम" नामक वेब पोर्टल स्थापित किया गया है। जिसका कार्य व्यापारिक कम्पनियों की सभी समस्याओं से सम्बन्धित प्रश्नों का समाधान करना है।

इस योजना पर पूरा नियन्त्रण भारत की केन्द्रीय सरकार का है। इस योजना का प्रतीक चिन्ह एक विशाल शेर है जो कई पहियों पर चल रहा है। पहियों पर चलता शेर–हिम्मत, मजबूती, दृढ़ता एवं बुद्धिमता को इंगित करता है एवं शक्तिपूर्ण प्रगति और सुनहरे भविष्य का प्रतीक है। यह अभियान प्रख्यात देश भक्त, दार्शनिक एवं राजनीतिक व्यक्तित्व के धनी पंडित दीन दयाल उपाध्याय को समर्पित किया है। जिनका जन्म 25 सितम्बर 1916 में हुआ था।

इस अभियान की घोषणा के बाद कई बड़े विदेशी उद्योगपतियों ने भारत में निवेश करने की घोषणा की है जिसमें से कुछ निम्न हैं।

- जनवरी 2015 में स्पाइस समूह ने उत्तर प्रदेश में 500 करोड़ रूपये की लागत से मोबाइल फोन उत्पादन यूनिट लगाने की घोषणा की। उस पर कार्य जारी है।
- सैमसंग कम्पनी भारत के विभिन्न शहरों में दस सैमसंग स्कूल खोलेगी।
- हिताची ने अपने कर्मचारियों की संख्या में (भारतीय यूनिट में) 3000 की वृद्धि की एवं चेन्नई में अपना आटोघटक संयन्त्र खोला है।
- हुवावेई ने फरवरी में बैंगलूरू में अपना एक अनुसंधान विकास परिसर खोला है जिसमें 1700 लाख अमेरिकी डालर का निवेश किया है।
- अप्रैल 2015 में एयरबस भारत में 2 बिलियन अमेरिकी डालर खर्च करने की घोषणा की है।
- सैमसंग ने नोएडा स्थित इकाई में जेड–1 मॉडल बनाने का कार्य शुरू कर दिया है।
- रूस का इरकुट कार्पोरेशन लड़ाकू विमान में लगाए जाने वाले कुल 332 कम्पोनैंटों के लिए तकनीकी हस्तांतरण करेगा
- समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने झींगा किसानों को झींगा अन्डों की आपूर्ति करने का वादा किया है।

भारत को लगभग दो वर्षों की अवधि के दौरान **563 बिलियन अमेरिकी डालर का प्रत्यक्ष** विदेशी निवेश प्राप्त हो चुका है। हाल ही में 13 फरवरी, 2016 को मुम्बई स्थित बान्द्रा कुर्ला काम्पलैक्स में "मेक इन इन्डिया सप्ताह" मनाया गया जिसमें 2500 अन्तर्राष्ट्रीय एवं 8000 घरेलू विभिन्न क्षेत्रों की औद्योगिक इकाइयों ने भाग लिया। इसमें 168 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

**राष्ट्र विकास में मेक इन इन्डिया की भूमिका–**

इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय युवा वर्ग को कुशल बनाना तथा उनके लिए रोजगार के नए अवसरों का सृजन कर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ–साथ उसे वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाना एवं देश को विकसित बनाकर आत्मनिर्भर बनाना है। राष्ट्र के विकास में इसका योगदान निम्न प्रकार होगा।

**1– आर्थिक विकास –** बिना आर्थिक विकास के देश का विकास संभव नहीं है। आर्थिक विकास के लिए पूंजी का होना अत्यन्त आवश्यक है यह पूँजी मेक इन इन्डिया के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ० डी० आई०) के माध्यम से आएगी। वर्तमान में भारतीय औद्योगिक इकाइयाँ सकल घरेलू उत्पाद (जी० डी० पी०) का केवल 16% ही भाग बनाती हैं। इसकी भागीदारी को वर्ष 2022 तक बढ़ा कर 25 प्रतिशत तक किया जाएगा। जिससे देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।

**2– कौशल विकास द्वारा तकनीकी विकास –** इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2020 तक 50 करोड़ युवा वर्ग को उनकी क्षमता एवं उद्योग की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रोजगार परख तकनीकी शिक्षा मिलने पर जहाँ एक ओर युवा वर्ग अपनी रूचि के विषय में पारंगत होकर अपनी सम्पूर्ण सकारात्मक ऊर्जा से स्वयं एवं समाज का कल्याण करेगा वहीं दूसरी ओर देश में नई तकनीकों का भी विकास होगा। इसके लिए भारत के कई शहरों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएंगे जिसमें उस शहर में लगी औद्यौगिक इकाइयों की आवश्यकता का भी ध्यान रखा जाएगा। जिससे तकनीकी विकास के साथ–साथ उत्पादित माल की गुणवत्ता भी बढ़ेगी।

**3– रोजगार के नए अवसर –** भारत की बढ़ती जनसंख्या के कारण आने वाले वर्षों में करोड़ों भारतीयों को जीविका हेतु विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी की आवश्यकता होगी। नये–नये उद्योग खुलने तथा पुराने उद्योगों की स्थिति सुधरने से रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इस योजना में प्रत्येक वर्ग को रोजगार के अवसर देने का प्रावधान है। युवावर्ग तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर छोटे निवेश से अपना रोजगार शुरू कर उन्हें बड़े आर्थिक संस्थानों में बदल सकेगा। जिससे वह अपने एवं अन्य युवकों को रोजी–रोटी के साधन प्रदान कर सकेगा। अकेले सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में ही 8000 के लगभग कम्पनियाँ आएंगी जिसमें 10 वर्षों के दौरान 11 करोड़ रोजगार के नए अवसर मिलने की संभावना है।

**4– उद्योगों का विकास –** इस योजना के द्वारा नए–नए विदेशी उद्योग ही नहीं खुलेंगे अपितु पुराने घाटे में चल रहे घरेलू उद्योगों को भी जीवनदान मिलेगा। घाटे में चल रहे भारतीय उद्योग का कुछ हिस्सा निजी कम्पनियों को बेचा जाएगा जिससे राजस्व उत्पन्न होने के साथ–साथ उनको विस्तृत होने का सुनहरा अवसर प्राप्त हो सकेगा। देश के विकास में अहम भूमिका निभाने वाले लघु मध्यम उद्योग जैसे हस्त शिल्प हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, हस्तकला को भी बढ़ने के अवसर मिलेंगे। "मेक इन इन्डिया" के माध्यम से इनसे जुड़े कारीगरों को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण एवं अन्य जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी जिससे वे अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर देश की जरूरत को भी पूरा करेंगे साथ ही साथ विदेशों में भी अपना माल बेच कर समृद्ध हो सकेंगे। पांरपरिक व्यावसायों जैसे–बढ़ई, मोची, दर्जी नर्सों राजमिस्त्री, निर्माण एवं परिवहन से जुड़े कारीगरों, वस्त्र, आभूषण डिजाइनर एवं पर्यटन से जुड़े लोगों का भी कौशल विकास किया जाएगा। जिससे वे तो लाभान्वित होंगे ही साथ ही देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।

**5– मानव संसाधन का विकास –** राष्ट्र के विकास में मानव संसाधन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। **रिचर्ड टी गिल** के अनुसार किसी भी राष्ट्र का आर्थिक विकास प्रत्येक वर्ग की भागीदारी पर निर्भर करता है। इस योजना में यह भी ध्यान रखा गया है कि प्रत्येक क्षेत्र के उद्योगों को फलने–फूलने के अवसर मिलें ताकि विभिन्न विषयों के ज्ञाताओं को उनके ही विषय में रोजगार के अवसर प्राप्त हों जिससे वह उसमें विश्व स्तर के अनुसंधान भी कर सकेंगे। इससे आधुनिक तकनीक का निर्माण एवं प्रयोग हो सकेगा एवं भारत में ही मानव संसाधन इतना होगा कि वह देश की जरूरत को भी पूरा करेगा एवं विदेश की माँग को भी पूर्ण करने में सक्षम होगा।

**6– कृषि एवं गाँवों का उत्थान –** भारत की 70 प्रतिशत जनता गाँवों में बसती है जो देश के आर्थिक विकास की रीढ़ है। "मेक इन इन्डिया योजना" में खेती के नए संसाधन, उन्नत बीज

का अविष्कार एवं फसलों की कटाई बुआई एवं भंडारण के आधुनिक तरीके अपनाए जाएँगे जिससे देश खाद्यानों की पूर्ति घरेलू उत्पाद से करेगा। जिससे इस क्षेत्र में आयात का अतिरिक्त खर्च नहीं झेलना पड़ेगा साथ ही साथ उत्तम गुणवत्ता वाले माल को निर्यात कर राजस्व भी प्राप्त हो सकेगा। सिंचाई के आधुनिक तरीके जैसे ड्रिप सिंचाई फव्वारे वाली सिंचाई द्वारा कम जल से अधिक पैदावार होगी। खेती से जुड़े युवकों को भी उसमें नए रोजगार मिलेंगे। जिससे गाँवों का उत्थान होगा।

**7– शहरों एवं पर्यटन का विकास** – इस योजना के अर्न्तगत भारत के सौ शहरों को स्मार्ट शहर बनाया जाएगा। वर्तमान में 25 शहरों को चुना गया है उनमें से नौ शहरों को 2019 तक तैयार किया जाएगा। इन शहरों को सड़कों, परिवहन एवं स्वच्छता की दृष्टि से सक्षम बनाया जाएगा जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। स्मार्ट शहर विदेशी निवेशकों को भी आकर्षित करेंगे। इसके लिए बड़े–बड़े उद्योगपति शहरों को गोद लेकर उनका नवनिर्माण करेंगे।

**8– प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण** – कोई भी राष्ट्र प्राकृतिक संसाधनों के बिना विकास नहीं कर सकता। लुईस के अनुसार–"समृद्ध समाज ही अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयुक्त उपयोग कर सकता हैं आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा एवं तकनीक में अकुशल राष्ट्र अपने संसाधनों का दुरूपयोग ही करता है।" जापान एक ऐसा देश है जिसके संसाधन सीमित हैं परन्तु उसने नई–नई तकनीक का विकास कर उन संसाधनों का उपयोग कर अपने को समृद्ध एवं शक्तिशाली बनाया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस योजना के अन्तर्गत ऐसे उद्योग को 10 प्रतिशत की कर–छूट देने का प्रावधान है जो ऐसे उपकरण बनाएंगे जो पर्यावरण प्रदूषण को नियन्त्रित करने वाली तथा ऊर्जा एवं जल की बचत करने वाले हों।

**9– भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक मान्यता के अवसर** – भारतीय उत्पाद गुणवत्ता वाले होने के कारण विश्व बाजार में बिकेंगे जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलने के साथ–साथ राजस्व में भी वृद्धि होगी। इस योजना में भारतीय उत्पाद को पेटेंट कराने, ट्रेड मार्ग का अधिकार, कापीराइट का अधिकार दिलाने का भी प्रावधान है जिससे देश में निर्मित वस्तुओं को विदेशी अपना बता कर बेच नहीं सकेंगे।

**10– राष्ट्रीय सुरक्षा में सुदृढ़ता** – सरकार ने 25 क्षेत्रों में से केवल 3 क्षेत्रों अंतरिक्ष–अंतरिक्ष कार्यक्रम में 74%, रक्षा क्षेत्र में 49% तथा मीडिया में 26% की ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दी है शेष 23 क्षेत्रों में यह निवेश 100% होगा। सुरक्षा के अधिक से अधिक उपकरण देश में ही बनने के कारण राष्ट्र हथियारों एवं सुरक्षा उपकरणों के आयत कर एवं खरीदर से मुक्त होगा तथा सुरक्षा और भी मजबूत बनेगी।

**11– सामाजिक विकास** – उद्योगों के खुलने, रोजगार की वृद्धि तथा व्यापार में आसानी होने के कारण भारत की बौद्धिक, व्यापारिक संपदा विदेश में पलायन नहीं करेगी जिससे परिवार खुशहाल रहेंगे आम आदमी की आय का स्तर बढ़ने तथा देश में बने उत्पाद एवं जरूरत की वस्तुएँ आसानी से कम दाम में उपलब्ध हो सकेंगी। महंगी दवाइयाँ, बीज, उपकरण सस्ते होने से मनुष्य को आर्थिक लाभ तो मिलेगा ही मनुष्य स्वास्थ्य एवं तनाव मुक्त रह सकेगा। प्रसन्नचित्त समाज परिवार को भी नियन्त्रित करता है। जिससे जनसंख्या में वृद्धि पर भी रोक लगेगी। देश का समाजिक ढाँचा सुदृढ़ हो सकेगा।

**12– आत्म निर्भर राष्ट्र निर्माण** – देश में ही प्रत्येक क्षेत्र में वस्तुओं के निर्माण से वस्तुओं का उत्पादन देश की जरूरत को पूर्ण करेगा जिससे प्रत्येक क्षेत्र में देश की दूसरे देश पर निर्भरता घटेगी तथा भारत एक निर्माता राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाने में सक्षम होगा। भारत आत्मर्निभर होकर विकसित राष्ट्र कहलाएगा।

इसमें किंचित भी संशय नहीं कि यह योजना राष्ट्र निर्माण में ब्रह्मास्त्र का कार्य करेगी। परन्तु यह ब्रह्मास्त्र अपने लक्ष्य तक पहुँच सके इसके लिए भारत के राजनीतिज्ञों को दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ प्रशासनिक तन्त्र को क्षमता प्रदान करनी होगी निर्माण की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करने वाले घटकों पर पैनी दृष्टि रखनी होगी। व्यवसाय को शुरू करने एवं चलाने के लिए उपयुक्त माहौल बनाना होगा, नए अनुसंधान विश्व मंच पर खरे उतर सके ऐसे यत्न करने होंगे, पर्यावरण संरक्षण पर सजगता एवं जागरूकता रखनी होगी। इस अभियान की शुरूआत "मेड इन चाइना" के साथ हुई है। अतः इसकी तुलना सदा इस अभियान से होगी। चीन की सर्वोच्चता को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उत्पादों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखना होगा। इस अभियान की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि भारत के उत्पाद विदेशी बाजार की उम्मीद पर खरे उतरें तभी दुनिया भारतीय उत्पादों पर निर्भर करेगी एवं राष्ट्र के विकास में "मेक इन इन्डिया" मील का पत्थर साबित होगा।